बाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम. भोपाल

1941

और अन्य (अर्चना पुरी, जे.)

अर्चना पुरी से पहले, जे.

बाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड-ए पेपेलेंट

बनाम

भोपाल और अन्य-उत्तरदाता 2010 का एफ. ए. ओ. सं. 6839

24 नवंबर, 2022

(पैरा 9) ने आगे कहा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 147 (4) और (5) के तहत आवश्यक प्रावधानों का अनुपालन करना होगा-पंजीकरण प्राधिकरण को नीति के रद्द होने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। (पैरा 11) आगू अभिनिर्धारित कयल गेल जे शिकायतकर्ताकेँ न्यायसंगत क्षतिपूर्ति देल जयबाक चाही।

(पैरा 28)

याचिकाकर्ता की ओर से वकील रजनीश मल्होत्रा ने कहा, T.P.Singh, प्रत्यर्थी संख्या 1 के लिए अधिवक्ता।

(1) वर्तमान अपील में चुनौती मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 16.08.2010 के पुरस्कार के लिए है, जिससे प्रतिवादी No.1-claimant भोपाल को एक मोटर वाहन दुर्घटना में लगी चोटों के कारण मुआवजा दिया जाता है, जो 15.04.2008 पर हुई थी। (2) प्रस्तुत साक्ष्य के मूल्यांकन पर, विद्वत न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी नंबर 1-दावेदार को रुपये की सीमा तक का मुआवजा देने का आदेश दिया था और मुआवजे का भुगतान करने का दायित्व आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा को तय किया गया था।

2022(2)

1942

'दराज द्वारा भुगतान रोक दिया गया' के कारण अपमानित किया गया। यह है। प्रस्तुत किया कि संबंधित बैंक ने Ex.R-3 के माध्यम से 'दराज द्वारा भुगतान रोक दिया गया' के कारण चेक वापस कर दिया था, जो दिनांकित 18.06.2007 है। इसके बाद, बीमा कंपनी ने विजेंद्र कुमार को चेक के अपमान के बारे में Ex.R4 के माध्यम से सूचित किया था, जो कि 22.06.2007 दिनांकित है। हालाँकि, दुर्घटना 15.04.2008 पर हुई थी।

जैसा कि बाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम. भोपाल

1943

और अन्य (अर्चना पुरी, जे.)

(9) जहां किसी अधिकृत बीमाकर्ता द्वारा बीमा पॉलिसी जारी की जाती है, प्रीमियम के भुगतान के लिए चेक की प्राप्ति पर और इस तरह के चेक का अनादर किया जाता है, तो उस देयता के संबंध में तीसरे पक्ष को क्षतिपूर्ति करने के लिए अधिकृत बीमाकर्ता का दायित्व, जो उस पॉलिसी में शामिल है और उसे मोटर वाहन अधिनियम की धारा 147 (5) और 149 (1) के प्रावधानों के कारण मुआवजे के पुरस्कार को पूरा करना होता है, जब तक कि अधिकृत बीमाकर्ता द्वारा बीमा पॉलिसी रद्द नहीं की जाती है और इस तरह के रद्द होने की सूचना दुर्घटना से पहले बीमित व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाती है। दूसरे शब्दों में, जहां किसी अधिकृत बीमाकर्ता द्वारा किसी वाहन को कवर करने के लिए बीमा पॉलिसी जारी की जाती है, चेक की प्राप्ति पर, प्रीमियम के लिए भुगतान किया जाता है और चेक का अनादर हो जाता है और वाहन की दुर्घटना होने से पहले, ऐसी बीमा कंपनी बीमा पॉलिसी को रद्द कर देती है और इसकी सूचना मालिक और अन्य अधिकारियों को भेजती है, बीमा कंपनी की तीसरे पक्ष को क्षतिपूर्ति करने की देयता, जिसे वह पॉलिसी कवर करती है, समाप्त हो जाती है और बीमा कंपनी उसके संबंध में मुआवजे के पुरस्कारों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। (10) अब, हाथ में मामले की ओर इशारा करते हैं। चेक, जिस पर बीमा कंपनी द्वारा भरोसा किया जाता है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वह प्रीमियम के भुगतान के लिए जारी किया गया था, Ex.R2 दिनांकित 13.06.2007 है। प्रमाणपत्र-सह-पुलिस अनुसूची की प्रति Ex.RX है। उसी के करीबी अवलोकन से पता चलता है कि प्रीमियम का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जिसका मालिक द्वारा चेक के माध्यम से भुगतान किया गया है। अन्यथा, यह चेक Ex.R2 एक व्यक्ति, कुलदिप कुमार द्वारा जारी किया गया था और यह Rs.29,826/- की राशि के लिए है, जबकि Ex.RX के अनुसार, कुल अंतिम प्रीमियम राशि आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा है।

2022(2)

1944

1 2012(2) आर. सी. आर. (सिविल) 197 2 2008 एसीके 581 (एससी)

बाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम. भोपाल

1945

और अन्य (अर्चना पुरी, जे.)

दावे को संतुष्ट करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ”

(13) इस प्रकार व्यक्त किए गए उपरोक्त दृष्टिकोण के आलोक में, पारस के मामले (उपरोक्त) में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि 'सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बीमा कंपनी का दायित्व केवल तभी रद्द किया जाता है जब सभी संबंधितों को बीमा पॉलिसी के रद्द होने के बारे में सूचित किया गया हो। तत्काल मामले में ऐसा नहीं हुआ (उक्त प्राधिकरण में विचाराधीन मामले में)। सटीक रूप से, इस खाते पर, बीमा कंपनी को मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। (14) मोटर वाहन अधिनियम अपने आप में तीसरे पक्ष के लिए एक लाभकारी कानून है। इसी को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि सार्वजनिक स्थानों पर चलने के लिए वाहन का बीमा प्रकृति में अनिवार्य है। उसी के आलोक में, यह निहित है कि बीमा कंपनी मालिक/बीमित व्यक्ति को बीमा कवरेज रद्द करने की जानकारी के साथ-साथ यातायात से निपटने के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण और उपयुक्त पुलिस प्राधिकरण सहित सभी संबंधितों को सूचित करेगी। अधिनियम की योजना के अनुसार, इस तरह का आश्वासन न केवल बीमित व्यक्ति को दिया जाना है, बल्कि तीसरे पक्ष को भी दिया जाना है, जिसे सड़क दुर्घटना के कारण चोट लगी है या जिसकी मौत हो गई है। वे बीमाकर्ता और बीमित व्यक्ति के बीच अनुबंध के आयात, अवधि और विस्तार के बारे में नहीं जानते हैं। इसके अलावा, वे किसी भी चूक के बारे में नहीं जानते हैं। उनका मानना है कि जब कोई वाहन सार्वजनिक स्थान पर चलता है, तो उसके पास चलाने के लिए सभी वैध दस्तावेज होते हैं। ऐसे वैध दस्तावेजों में से एक बीमाकर्ता और बीमित व्यक्ति के बीच तीसरे पक्ष के जोखिम को कवर करने के लिए बीमा का अनुबंध है। बीमाकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह न्यायाधिकरण के समक्ष बचाव करे कि उसने न केवल बीमा कवरेज को रद्द कर दिया है और बीमित व्यक्ति को सूचित किया है, बल्कि साथ ही सभी संबंधित लोगों को वाहन को सड़क पर चलने से रोकने के लिए भी सूचित किया है, अन्यथा वह तीसरे पक्ष को मुआवजे का भुगतान करने के दायित्व से बच नहीं सकता है। जब अधिनियम के तहत बीमा कवरेज अनिवार्य है, तो इसके दो गुना कर्तव्य हैं अर्थात रोकथाम और मुआवजा। जब वे रोकथाम के अपने कर्तव्य का निर्वहन कर लेते हैं, उपयुक्त अधिकारियों को सूचना द्वारा कवरेज के अभाव में, उनकी देयता को समाप्त किया जा सकता है और अधिकारी बीमा कवरेज नहीं होने के कारण सार्वजनिक स्थान से ऐसे वाहन की जब्ती सुनिश्चित करने के लिए सख्ती से उत्तरदायी होंगे। उन्हें नोटिस देने का मतलब है जनता को नोटिस देना। इसके अभाव में, किसी बीमा कंपनी को किसी तीसरे पक्ष को मुआवजे का भुगतान करने के उनके दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, कानून के तहत प्रावधानों को आवश्यक चेक के अपमान के लिए बीमा अनुबंध को रद्द करने के बारे में बीमाकृत को बीमाकृत की एकल जानकारी के माध्यम से निराश नहीं किया जा सकता है।

यह सख्त आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा है।

2022(2)

1946

(18) इसके अलावा, अपीलार्थी के लिए आगे विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि मुआवजा, जिस पर न्यायाधिकरण द्वारा काम किया गया है, बहुत अधिक है और इसे कम करने की आवश्यकता है। हालाँकि, इस निवेदन का कोई आधार नहीं है और इसे अस्वीकार करने की आवश्यकता है। (19) पेश किए गए साक्ष्य से, यह स्थापित होता है कि प्रतिवादी No.1-claimant को दुर्घटना में कई चोटें आई थीं। अपने हलफनामे Ex.PW6/A में, उन्होंने अपने शरीर पर कई गंभीर और गंभीर चोटों के बारे में स्पष्ट रूप से बयान दिया है। उन्हें कंपाउंड फ्रैक्चर, शाल्फ्ट फीमर, टिबिया में फ्रैक्चर का सामना करना पड़ा था और ऑपरेशन के बाद उनका दाहिना पैर काट दिया गया था और वे स्थायी रूप से विकलांग हो गए थे। यहां तक कि हैदराबादी अस्पताल, पानीपत के ऑर्थोपेडिक सर्जन पीडब्लू-1 Dr.Ritesh सिंह ने भी 15.04.2008 पर अस्पताल में प्रतिवादी No.1-claimant के भर्ती होने और 10.05.2008.He पर अस्पताल से छुट्टी मिलने के बारे में एमएलआर Ex.P1 साबित किया है और उन्होंने यह भी बताया है कि रोगी का कई चोटों के लिए ऑपरेशन किया गया था। उन्होंने चोटों का विवरण दिया। उन्होंने पांच बार ऑपरेशन करने के बारे में भी स्पष्ट रूप से अपदस्थ किया। निर्वहन सारांश Ex.P2 है। उन्होंने आगे प्रतिवादी संख्या 1-दावेदार के बारे में गवाही दी है कि उन्हें फिर से 20.05.2008 पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 26.05.2008 पर छुट्टी दे दी गई है और फिर से 07.08.2009 पर भर्ती किया गया है और 10.08.2009 पर छुट्टी दे दी गई है और छुट्टी के सारांश को Ex.P10 और Ex.P11 के रूप में साबित किया है। यहां तक कि बीज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से भी चिकित्सा बिलों को साबित किया गया है।

भोपाल

1947

और अन्य (अर्चना पुरी, जे.)

(20) यह उल्लेख करना उचित है कि दावेदार का दाहिना पैर घुटने के नीचे से काट दिया गया था। (21) उपरोक्त साक्ष्य पर विचार करते हुए, विद्वत न्यायाधिकरण ने दर्द और पीड़ा के कारण, विशेष आहार और परिचारक की व्यस्तता के कारण, Rs.60,000/- की सीमा तक, Rs.40,000/- की सीमा तक मुआवजा प्रदान किया था। इसके अलावा, विद्वत न्यायाधिकरण ने गुणक के संरचित सूत्र को लागू करते हुए आय के नुकसान पर काम किया था और मृतक की आय को 3,900/- रुपये प्रति माह लिया था, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के लिए निर्धारित किया गया था, प्रासंगिक समय पर और इस तरह से काम करते हुए, विकलांगता की गिनती पर मुआवजे को 3,900/- रुपये लिया गया है। इसके अलावा, उनके इलाज पर हुए खर्च का कुल बिल रु. 1,46,460-माना जाता है। उसी का कुल बनाते समय, रुपये 7,21,010-की सीमा तक मुआवजा दिया गया था।

(22) श्रीमती में। सरला वर्मा बनाम दिल्ली ट्रांसपोर्ट

निगम और ए एन आर। 3 , उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायसंगत क्षतिपूर्ति पर्याप्त क्षतिपूर्ति है और पुरस्कार केवल इतना ही होना चाहिए-'कम नहीं और अधिक नहीं'। दुर्घटना के बाद उसके जीवन में जो अप्रत्याशित और आकस्मिक मोड़ आते हैं, उनके साथ बातचीत करने के लिए हमेशा उचित प्रतिफल प्रदान करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसलिए, जबकि अदालतों द्वारा दिया गया धन शायद ही घायल पीड़ित (जो जीवन की सामान्य सुविधाओं से वंचित है और दूसरों पर बोझ होने की बेचैनी से पीड़ित है) की वास्तविक पीड़ा का निवारण कर सकता है, अदालतें 'न्यायसंगत मुआवजा' देकर ऐसे दावेदार की आत्म-गरिमा को बहाल करने का वास्तविक प्रयास कर सकती हैं। (23) उसी तर्ज पर क्षतिपूर्ति देने का प्रयास करते हुए, विशेष रूप से, प्रतिवादी को लगी चोटों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर कहा गया है, क्षतिपूर्ति 3 2009 (3) आर. सी. आर. (सिविल) 77 आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

1948

विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया 'न्यायसंगत मुआवजा' है, जो बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुत किए गए किसी भी पैमाने को कम नहीं करने का आह्वान करता है। (24) उपरोक्त अवलोकन के आलोक में, वर्तमान अपील बिना किसी योग्यता के है और इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है। अमृता गर्ग